

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक २२ फरवरी, 2017

विषय— मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सृजित 26 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-105/XXXVI(1)/2016-234/2001 T.C.-III दिनांक 20.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु सृजित 26 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं०-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन-00—आयोजनेत्तर-102—उच्च न्यायालय-03—उच्च न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 सपष्टित कार्यालय ज्ञाप सं०-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय



(आलोक कुमार वर्मा)

सचिव

संख्या- 63 /XXXVI(1)/2017-234/2001 T.C.-III तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कार्याधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अनुभाग-7/कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र कौशिक)  
अपर सचिव